PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Wednesday, 23rd November 2011, Page: 10
Width: 22.44 cms Height: 11.73 cms, Ref: pmin.2011-11-23.48.116

नशीली दवाओं में इस्तेमाल रसायनों पर और कड़ा नियंत्रण

आगरा, 22 नवंबर (भाषा)। दवाइयों के गैरकानूनी व्यापार को काबू पाने के लिए भारत कृत्रिम नशीली दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के उत्पादन पर नियंत्रण और सख्त करेगा। यह बात वित्त सचिव आरएस गुजराल ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय दवा कानून प्रवर्तन एजंसियों के प्रमुखों की बैठक में कही।

गुजराल ने कहा कि एंफेटामाइन किस्म के उत्प्रेरक (एटीएस) के उत्पादन के लिए एफेड्रिन और स्यूडो एफेड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार इन रसायनों पर नियंत्रण और कड़ा करने पर विचार कर रही है। ये रसायन कृत्रिम नशीली दवाएं बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत-पाक सीमा और भारत-म्यामां सीमा के दायरे में गैरकानूनी व्यापार लगाम लगाने के लिए इन दोनों रसायनों को विशिष्ट तत्व के तौर अधिसूचित किया गया है।

यूएनआईडीसी ने एटीएस को भांग के बाद विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा करार दिया है। इसमें कहा गया कि इस दवा व्यापार और आपराधिक मुनाफे से विश्व भर में सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा है।

वित्त सचिव ने कहा कि भारत दवा के गैरकानूनी कारोबार और प्रसार के रोकने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय दवा नियंत्रण सम्मेलनों के तहत तय मानदंडों के अनुरूप अपने कानूनी ढांचे में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में अफीम की बढ़ती पैदावार पर जाहिर की और नशीली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए इस देश के सदस्य देशों के बीच बेहतर संयोजन की जरूरत पर बल दिया।

गुजराल ने 2011-12 के लिए तय विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार शेयर बाजार में अनिश्चितता के बावजूद सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के विकल्प का आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि 40 हजार करोड़ के लक्ष्य को छोड़ने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि कई तरह के विकल्प हैं और सारे विकल्पों का खाका तैयार कर लिया गया है। 40 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य अभी छोड़ा नहीं गया है। वास्तविक विनिवेश बाजार की स्थिति पर निर्भर है।

गुजराल ने कहा कि अगर बाजार के हालात खराब होते हैं तो खराब माहौल में विनिवेश करना अनुचित होगा। लेकिन बाजार में किसी भी वक्त सुधार हो सकता है। चालू वित्त वर्ष के सात महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ पावर फाइनेंस कारपोरेशन की हिस्सेदारी बेच कर 1145 करोड़ रुपए जुटा पाए हैं। आशंका जताई जा रही है कि 2011-12 के तय 40000 करोड़ रुपए के भारी-भरकम विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।

वित्त सचिव ने कहा कि शेयर बाजारों में हो रही उठा-पटक के कारण सरकार को मजबूरन सरकारी उपक्रमों में प्रस्तावित हिस्सेदारी की बिक्री में देरी करनी पड़ी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी बेच कर 22 हजार करोड़ रुपए जुटाए थे।

बैंक पुनर्पूंजीकरण के बारे में गुजराल ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी बैंकों को पर्याप्त पूंजी मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त धन मुहैया कराने में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास बजटीय आवंटन की सुविधा है। जरूरत पड़ने पर पूंजी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2011-12 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6000 करोड़ रुपए अलग किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया सहित कई बैंकों को ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी।

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के बारे वित्त सचिव ने कहा कि वित्त मंत्रालय प्रत्य कर संहिता विधेयक पर संसद की स्थायी समि की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। डीटीसी क एक अप्रैल, 2012 से लागू किया जाना है। य आयकर कानून,1961 का स्थान लेगा। उन्हों कहा कि स्थायी समिति शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करती तो यह तय अवधि पर लागू होगा।

Regulatory